''तलाश के लक्ष्य एवं उद्देश्य''

1. एक अराजनैतिक, अहिंसात्मक, वैचारकि अभियान है।
2. आमलोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सामाजिक जीवन के सभी आयामों के कार्य-कलापों में सुधार लाने का कार्य करेगा।
3. प्रत्येक नगरिक में 'सच को सच' एवं 'गलत को गलत' कहने की शक्ति पैदा करेगा।
4. प्रत्येक नागरिक को वाजिब तरीके से प्रतिदिन अपनी आय में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
5. रचनात्मक सामूहिक सोच का निर्माण करने को कृत संकल्प है।
6. संबंधित सक्षम अधिकारियों/व्यक्तियों को सही दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा।
7. किसी प्रकार की सीधी सेवा नहीं प्रदान करेगा।
8. पूरे भारत में आम व्यक्ति को पहरुए की तरह जागरूक करने का काम करेगा। यह किसी भी क्षेत्र/ प्रकार की गलती दिखने पर उसे अहिंसात्मक ढंग से ठीक करेगा।
9. सदस्य बनने हेतु कोई शुल्क नहीं होगा एवं सदस्य अवैतनिक कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करेंगे।
10. इसका अपना कोई निधि/कोष नहीं होगा। संस्था के छोटे-मोटे खर्च सदस्यगण मिलकर वहन करेंगे।
11. इसका अन्य गैर सरकारी संगठन की तरह निबंधन नहीं होगा एवं इसमें कोई अध्यक्ष, सचिव अथवा कार्यकारिणी नहीं होगा।

कोष, कुर्सी, कौन! तीनों गौण!!

तलाश

'बूंदें'-3

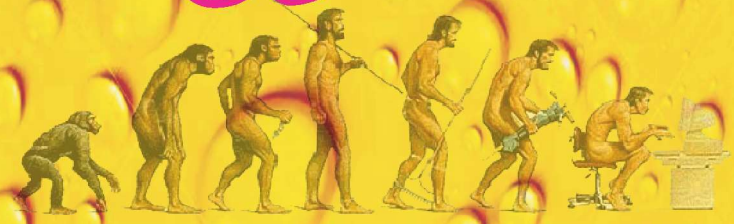

न्यायपालिका, मिडिया, आजादी

प्रो. (डॉ.) विश्वेन्द्र कुमार सिन्हा

समर्पण
2020

उन गुड्डे एवं गुड़ियों को -
जो दिलोजान से प्यार किये जाने पर जीवन्त हो उठेंगे।

तलाश के लोग

आमंत्रण

आत्मन्

आप जहाँ भी हैं, जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, करते चलें, अन्य लोगों को भी अपनी सृजनात्मक उर्जा से उत्प्रेरित करते चलें, 'तलाश' तो आपके मन– प्राण में है।

वृहत एवं त्वरित बदलाव के लिए आपका हमारा जुड़ना आवश्यक है।

मिलें तो सही।
बातें तो हों,
हर माह के प्रथम रविवार की बैठक में शामिल हों,

– 'तलाश' परिवार

सम्पर्क :	फोन नं॰
श्री प्रणव कुमार चौधरी	8969481918
डॉ॰ अविनाश प्रसाद	9934410252
श्री अजित कुमार सिन्हा	9334310425
ब्रिगे॰ के॰ एम॰ पी॰ सिंह	9801043097
श्री रवीन्द्र कुमार	9835454798
डॉ॰ विश्वेन्द्र कुमार सिन्हा	9931025029
श्री शिव कुमार	9135020199

स्थान : एच-3, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग पटना - 20

विषय सूची

		बूंदें
1.	तलाश परिचय	1 से 9 तक
2.	न्यायपालिका	10 से 54 तक
3.	मिडिया	55 से 70 तक
4.	दलगत राजनीति	71 से 86 तक
5.	आजादी	87 से 90 तक
6.	संकट	91 से 96 तक
7.	अन्यान्य/विचारणीय	97 से 112 तक
8.	गरीबी/बेरोजगारी	113 से 117 तक
9.	जागो ग्राहक	118 से 124 तक

Blank Page

01

1. आपसे मुखातिब

ये सिर्फ बूंदें हैं – एक दो पड़ जाने से ध्यान भी नहीं जायेगा, बहुत सारे मिलकर आपको भिंगो दे सकते हैं या फिर यूँ ही बह जायेंगे।

बूंदे क्षणिक हैं, कुछ सामयिक जो समय के साथ अप्रासंगिक हो जायेगें, कुछ दीर्घकालिक है, कुछ शाश्वत होने की तरफ हैं, कुछ अत्यन्त व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हैं, कुछ अनुभवगम्य, कुछ अन्य महानुभावों की समझ से प्रेरित (उनसे सविनय याचना के साथ)!

बूंदे जो इकाई है .... सागर की।

02

तलाश : क्या – क्यों ?

- 'तलाश' एक वैचारिक आंदोलन है।
- 'तलाश' वर्ष 2000 से कार्यरत Civil Society है जो देश, समाज की बेहतरी के लिए समर्पित है। इसमें हर तबके एवं स्तर के लोग हैं।
- निरपेक्ष, नि:स्वार्थ, पूर्वाग्रह रहित !
  अराजनैतिक और अहिंसात्मक।
  जिसका अपना कोई एजेण्डा नहीं।
  यहाँ 'कोष' 'कुर्सी', 'कौन' तीनों गौण है।
- यह कुछ लोगों की नि:स्वार्थ अभिव्यक्ति है, किसी से कोई विवाद नहीं।

03

- तलाश की विषय वस्तु पर जिनकी सहमति है उन्हें धन्यवाद; जिनकी असहमति है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद वे ही हमें दुबारा आत्मचिंतन और निरीक्षण का अवसर देते हैं।
- तलाश का कथ्य है-

→ गलत को गलत कहें।

→ अच्छे को अच्छा कहें।

→ अपनी आमदनी वाजिब तरीके से प्रतिदिन बढ़ाएँ।

→ रचनात्मक सामूहिक सोच का निर्माण करें।

→ सभी कार्य अराजनैतिक एवं अहिंसात्मक हों।

04

- 'तलाश' यथासम्भव सबों तक पहुँचना चाहता है; खासकर तमाम बुद्धिजिवीयों तक।
- आवश्यकता है विभिन्न भाषाओं में अनुबाद कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने की।
- हम तमाम लोग पहले एक व्यक्ति, फिर समाज और देशवासी हैं। इसके बाद ही कोई 'भेद' आता है।

तलाश : चिंतन

- न गद्य है, न पद्य है।
  सिर्फ कुछ कथ्य है।
  परन्तु तथ्य ही तथ्य है।

- न कर्म है, न धर्म है।
  सिर्फ एक क्रन्दन है।
  सिर्फ एक चिंतन है।
  गोबर है, खाद है।

कमल दल की आश है।

तलाश : चिंतन

3. भयानक दुष्चक्र है !
   प्रत्यक्ष या परोक्ष,
   पैसा ही चलता है ।
   पैसा ही शासक,
   पैसा ही नियंता है ।

   मुख्य या प्रधान हो,
   मंत्री या संतरी हो,
   चुनाव है, चुनावी फंड है, चुनावी वांड है।
   चुनावी 'दलबंदी' है,
   दलगत राजनीति है ।
   'दलों' (गैंगों) का ही शासन है,
   हम (जनता) तो बेमानी हैं ।

तलाश : चिंतन

4. पैसा ही ऊर्जा है ।
   ऊर्जा ही जीवन है ।
   क्रमिक विकाश है ।
   बुद्धि का राज है ।
   आत्मा का नाश है ।
   इसके लिए भ्रष्टाचार ही आचार है ।

5. पैसा निरपेक्ष है ।
   भावना से रहित है ।
   उर्जा का श्रोत है
   था तो एक 'कूपन'
   अब तो नियामक है ।

तलाश : चिंतन

6. पैसा ही गति है ।
   बाकी ''सबकुछ'' गतिहीन है ।
   इस ''सबकुछ'' में 'सोच' है,
   'विचार' है, 'बुद्धि और 'विवेक' है ।
   'इमान' और 'न्याय' है ।

7. पैसे के बिना समर्थ भी असमर्थ है ।
   जो पैसा विहीन है सब तरह से हीन है ।
   'पैसा' संगठित है । बाकी विखराव है ।

8. बिना पैसा अजब की बेवसी है।
   पैसे के कारण भी अजब अकुलाहट है।
   दंगा फसाद है। आतंक, नक्सलवाद है।
   पैसे के बिना क्या कोई उपाय है ?

बूंदें

09

तलाश : चिंतन

9. हम सब निष्क्रिय हैं। वेअसर हैं;
डॉक्टर - वकील है, इंजिनियर - ठेकदार हैं;
प्रोफेसर - विद्वान हैं;
लेखक - पत्रकार हैं, व्यापारी - उद्योगपति हैं;
प्रशासक और शासक हैं,
राजनीतिज्ञ हैं, पुलिस - मिलिट्री है।
सभी सिर्फ सुविधा के भागीदार हैं।
'कोई नृप हों हिं'
हमें क्या दरकार है !

बूंदें

10

न्याय

कानून का जन्म और विकास ।
पंच; काजी; आधुनिक न्यायपालिका

- 'दो' हुये तो 'मत भेद' हुआ।
  दोनों ने लड़कर फैसला कर लिया।
  एक ही जिंदा बचा।
- यह आदिम/जंगल/पशुबल प्रधान कानून मान्य नहीं हुआ तो 'तीसरे' का उदय हुआ ।
- स्पष्टत: इस 'तीसरे' की राय दोनों पक्षों पर वाध्यकारी होगी तभी व्यवस्था बनी रहेगी।
- यही 'तीसरा' पंच, काजी और न्यायपालिका हुई।
- 'नियमन' की शुरूआत हुई।

बूंदें

11

सामूहिक जीवन का आधार नियमन है ।
नियमन ही कानून बना, लगातार बनता ही जा रहा है।

- सबसे सशक्त 'विधायिका' बनी ।
- काम केवल कानून ही बनाना है ।
- व्यक्तिगत सामाजिक जीवन के हर बात पर हावि और प्रभावी ।
- कार्यपालिका बनी/कर्तव्य बना ।
- यहाँ कर्तव्य अधिकार बन जाता है, और अधिकार शोषण, भ्रष्टाचार और गिरावट का माध्यम बन जाता है ।

बूंदें

12

नियमन

- गलती के लिए कोड़े मारना अत्यंत त्वरित प्रभावी deterrent/न्याय/नियमन/निदान था ।
- 'सभ्य' (अधिकार सम्पन्न) को यह (कोड़े खाना) अस्वीकार्य लगा अत: समाप्त हो गया ।
- आर्थिक दण्ड कोड़े से कम नहीं है, परन्तु यह अनुपातिक नहीं है/होना चाहिए ।
- इस प्रकरण या अन्य कई प्रकरणों में यह असत्य/अन्यायपूर्ण हो जाता है ।
- इसका कारण आर्थिक असमानता है, जो सत्य है, शायद सनातन है ।
- अधिकार संपन्न/करोड़पति/अरबपति एवं विपन्न के फर्क को मिटाया नहीं जा सकता है ।
- दण्ड विधान एक कैसे हो सकता है ?

बूंदें

13

नियमन

- अर्थ दण्ड को समानुपातिक बनाने से बहुत-कुछ ठीक हो जायेगा।
- अर्थ दण्ड को समानुपातिक बनाने से यह deterrent का बढ़िया और ज्यादा कारगर तरीका हो जाएगा।

  परन्तु इसे कार्यालय–न्यायालय के कर्तव्य -अधिकार–भ्रष्टाचार के दुष्चक्र से बचाना होगा।

बूंदें

14

न्याय व्यवस्था

मुख्य दिक्कतें –

- इतनी देरी कि अक्सर न्यायपालिका का लक्ष्य ही पूरा नहीं होता।
- इतनी आदर्शवादिता कि हमारे देश-समाज के लिए Applicable नहीं होता। कमजोर वर्ग के लिए तो बिल्कुल नहीं।
- अस्पष्ट निर्णय/असंगत निर्णय।
- परस्पर विरोधी निर्णय, उसका न कोई सर्वे न समाधान।
- इतनी खर्चीली कि सामान्य व्यक्ति की पहुँच से बाहर; बड़े लोगों का आखाड़ा और उनके लिए हर जुर्म से निकलने का उपाय है।
- अनगिनत उदाहरण हैं।

क्रमशः

बूंदें

15

न्याय व्यवस्था

- आखों के सामने और जानकारी रहते, हुए भी अपने ही तंत्र के भ्रष्टाचार को कुछ नहीं करता।
- दूसरे मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेता है।
- महत्वपूर्ण/कठिन मुद्दे पर आँखें मूदे रहता है।
- न्यायिक भाषा इतनी क्लिष्ट कि समान्य जन को समझना मुश्किल।
- इतनी निरंकुशता कि अक्सर दायरा/और उद्देश्य भटक जाता है।
- सैन्य सेवा से लेकर तकनिकी/वैज्ञानिक विषयों पर निर्णय वैज्ञानिक/समाचीन नहीं रह पाता।
- Technicalities पर निर्णय – न्याय के उद्देश्य को दरकिनार कर देता है।
- न्याय की जगह कानून की जकड़न।

बूंदें

16

जजों की नियुक्ति-

- जजों की नियुक्ति – इतनी अलोकतांत्रिक अपारदर्शी कि स्वीकार्य नहीं।
- यदि हमारे राष्ट्रिपति, प्रधानमंत्री, सांसद, सभी समर्थ लोग संवैधानिक या अन्य पदों पर भी अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन करते तो क्या विगड़ता ?

  पारदर्शिता, विश्वसनीयता, लोकतांत्रिक विश्वास ?

नैसर्गिक न्याय–

कानूनी न्याय की विवेकपूर्ण विवेचना विद्वान जजों की जिम्मेदारी होनी चाहिए । किसी भी कानून/संविधान के प्रावधान की विवेचना लोग अपनी-अपनी तरह से कर सकते हैं, इसकी विविधता को कम करने के लिए एक Gauideline, नियामक संस्था होनी चाहिए ।

दिए गए विरोधाभासी Judgement को आगे के लिए एक करना आवश्यक है एवं ऐसा कम से कम हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

विरोधाभासी न्याय तो एक न्यायाधीश का न्याय हो जाता है - न्यायालय का नहीं ।

न्यायपालिका : निरंकुशता

- न्यायपालिका के सम्मान को सुनिश्चित करने एवं न्यायाधीशों के अहंकार और उसकी सीमाहीनता, जिसमें विधायिका भी लुप्त हो जाय; में आवश्यक संतुलन आवश्यक है ।
- स्वायत्तता एवं निरंकुशता में स्वविवेक/उत्तरदायित्व बोध का फर्क हैं ।
- निरंकुशता विधायिका या न्यायापालिका का ?
- किसी भी स्तर पर निरंकुशता ठीक नहीं है ।
- आपके द्वारा इस पर मनन और राय कायम करना आवश्यक है ।

वकील-वकालत

- न्याय के लिए नहीं, पेशे के लिए/पैसे के लिए ।
- कानून की जानकारी के कारण मुवक्किल को गलत सलाह देना, और मामले को उलझा देना ।
- वकीलों के कारण लोग अपनी बात सीधे न्यायाधिशों तक नहीं पहुँचा पाते ।
- वकालत ने न्यायप्रक्रिया को कब्जे में कर लिया है ।
- वकील मुवक्किल की सहायता न कर उसे विस्थापित कर देते हैं ।

तलाश द्वारा न्यायपालिका पर वार्षिक अधिवेशन 2018 ।

जो विषय वस्तु थी, आज भी/भविष्य के लिए भी उनता ही महत्वपूर्ण है :-

1. न्यायालय की philosophy.
   - अव्यवहारिक/काल्पनिक। आर्दश-वादिता की जगह व्यवहारिकता एवं परिवेश को स्थान मिलाना चाहिए ।
2. न्यायापालिका के निर्णय में व्यक्ति की आजादी (अभिव्यक्ति एवं अन्य) और सामाजिक जीवन की, मान्यताओं/आस्था में सामंजस्य होना चाहिए ।

3. प्राथमिकता का निर्धारण :-

क. न्यायालय में लम्बित करोड़ों केशों का निष्पादन एवं त्वरित न्याय व्यवस्था (की खोज)

या

मनुष्य की काम भावना, सबरीमाला इत्यादि का निर्धारण ?

ख. निर्णय में टेक्नीकेलिटी और कानून की प्रधानता

या

सामाजिक/व्यक्ति की सुरक्षा, संरक्षा के लिए विवेक का अधिकार न्यायधीशों को मिले ?

ग. कानून का पालन या न्याय का पालन ?

4. गलत आधार तलाशे जाते है ।

क. समलैगिंकता की स्वीकारोक्ति प्रगतिशीलता समझी जाय ?

ख. सबरीमाला, 497, 498A में उच्चतम न्यायालय के अन्य फैसलों को भी स्त्रियों के उत्थान के मद्दे नजर इसे आधुनिकता की मिशाल समझी जाय ? क्या इन मुद्दों पर सामाज/सामूहिक राय/मान्यतायें कोई मायने नहीं रखती ?

ग. ऐसे मामलों में निर्णय क्या न्यायाधीश रूपी एक व्यक्ति की मान्यता/उद्देश्य/अनुभव परिलक्षित नहीं हो जाता ?

5. गलत व्यक्तिगत आधार/मान्यता-

- ऐसे सांस्कृतिक/सामाजिक/परिदृश्य बदलने वाले वैयक्तिक मामलों पर विचार आम राय (National Referendum) से होना चाहिये या व्यक्तिगत मान्यता पर ?
- दो व्यक्तियों का साथ रहना एक बात है; उसे शादी करार देना अलग बात है।
- शादी हमारा एक संस्कार है ।
- शादी का उदेश्य देह का उपभोग नहीं अगली पीढ़ी को जन्म देना, पालन करना है ।

1. पश्चिमी देशों का अंधानुकरण, गतिशीलता नहीं आत्महीनता की निशानी है ? क्या हम जो कुछ हैं, हमारा जो कुछ है वह कम है और गलत है?
2. ऐसे कई समाज-देश हैं (पश्चिमी भी) जो समलैंगिकता को पूर्णतया नकारते हैं और उनके कानून काफी सख्त हैं ।
3. यह अफसोस जनक है कि आत्महीनता और अंधानुकरण की यह भावना, सामान्य मान्यताओं से अलग, नया कुछ कहने की ललक तथा कथित वुद्धिजीवियों अर्थ/अधिकार सम्पन्नों, पत्रकारों, सिनेमा, टीवी इत्यादि संचार माध्यमों से सम्बंधित लोगों में अधिक है ।
4. यह सब वे लोग अर्थोपार्जन के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने, 'सामान्य' से अपने को ऊपर समझाने के लिए करते हैं ।
5. व्यक्तिगत जीवन में वे सब स्वयं इसे नहीं स्वीकारते ।

- सामान्य जन सिर झुकाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है ।
- व्यक्तिगत स्वंतत्रता को पूर्ण, निर्बाध और क्षितिज तक ?
  - एक की, समर्थ की या सबों की?
  - सिर्फ वाचालों की या मूक की भी ?
- परन्तु इसकी निरर्थकता और गलत होने के बोध को स्वीकारा गया कि :-

"स्वतंत्रता वहीं तक जहाँ वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है ।"

यह तो आर्ष-वाक्य है ।

सभी पुरुष समानता :-

- अलग स्नानागार/शौचालय, रेल में अलग डिब्बे, हवाई अड्डों पर अलग जाँच इत्यादि की व्यवस्था सही है या गलत ?
- सभी खेलों जैसे ओलम्पिक, कुश्ती इत्यादि भी क्या एक साथ होने चाहिए ?
- ये प्रश्न महत्वपूर्ण है : इन्ही में सबरीमाला मंदिर व्यवस्था का जबाब निहित है, स्त्री-पुरुष की समानता का उत्तर भी है ।

समानता

- स्त्री एवं पुरुष एकाकी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में सक्षम हैं; परन्तु-
- स्त्री-पुरुष का साथ स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, एक दूसरे का पूरक है; एवं इसी में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सुरक्षा एवं आनन्द है ।
- एक की मानसिकता (सम लैंगिकता इत्यादि) को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहचान दी जा सकती है सभी पर कानून थोप देना; प्रोत्साहित (Promote) करना है, घातक है ।
- स्त्री/पुरुष सभी रूपों में समान है या पूरक ?

समानता

- किसी को किसी के साथ किसी भी भाव में रहने की कहाँ मनाही है ?
- समलैंगिक शादी अप्राकृतिक है । Absurd है ।
- हमारी स्थापित संस्कृति के विरुद्ध है ।
- यौन अपराध में वृद्धि होगी ।
- बच्चाबाजी के अपराधियों को सजा देना सम्भव नहीं होगा ।
- परिवारिक संरचना और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय जो particular case के लिए नहीं बल्कि सबों के लिए पारित होता है, जो अधिकांश को स्वीकार्य नहीं, follow भी नहीं होता है-सिर्फ उसी 'वाद' तक लागू होना चाहिए ।
- सामूहिक सोच का निर्माण करें ।

बूंदें

29

गलत आधार तलाशे जाते हैं :-

- 377 को एक प्राकृतिक व्यवस्था मानी गयी ।
- इस पर forensic विशेषज्ञों (जूरी) की राय महत्वपूर्ण है, न कि जज रूपी एक व्यक्ति की ।
- यदि समलैगिकता प्राकृतिक है तो–अन्य मानसिक sexual aberrations जैसे :
  - ❑ Incest जैसे–बेटी–बहन, बहु इत्यादि से सम्बंध बनाना?
  - ❑ Fetichism (स्त्रियों के वस्त्राभूषण इत्यादि से उतेजित व्यवहार)
  - ❑ Bestiality (पशुओं से संभोग करना) कैसे गलत है ?

ये मानसिक विकृतियाँ (sexual Aberration) सामयिक होते है एवं सामान्यत: उम्र के साथ स्वत: समाप्त हो जाते हैं ।

इन्हें समान्य घोषित करना इनको प्रेरित करना है ।

बूंदें

30

न्यायपालिका का सम्मान आवश्यक एवं अपरिहार्य सामाजिक व्यवस्था है।

- सामूहिक निर्णय प्रणाली, ज्यूरी व्यवस्था एवं जहाँ प्रभावी हो वहाँ Technical expert (Jury) की राय की निर्णायक भूमिका होनी चाहिए ।
- कानूनों का दुरुपयोग होता है, जैसे कि SC/ST Act, 498A, Rape, Me Too, सामान्य बात है, स्वीकार्य है ? या निरुपाय है ?
- असंतुलित कानून बनाना/व्याख्या गलत है सामाजिक व्यवस्था विकृत करने वाला है ।

बूंदें

31

दोहरे मानदण्ड–

Negligence जितना डाक्टरों/अभियंताओं /अन्य से होता है न्यायपालिका में उससे कम नहीं होता है ।

- न्यापालिका के दोहरे मानदण्ड – उदाहरण वकील बनाम पुलिस, तीस हजारी कोर्ट दिल्ली : 2019

देश के लिए/लोकतंत्र के लिए

- बहुत शर्मनाक एवं खतरनाक घटना हुई ।
- कानून को अपने हाथ में लेने के कारण वकीलों ने न मालूम कितनों को सजा दिलवायी होगी । यदि इन्हें कानून हाथ में लेने की सजा नहीं मिली तो अन्य को क्यों?

बूंदें

32

दोहरे मानदण्ड

- इस प्रकरण में सही एवं निष्पक्ष न्याय नहीं होना सीधे न्यायपालिका और कार्यपालिका का भिड़ंत है ।

निष्पक्ष न्यायपालिका का हल्का सा भी झुकाव (सम्बंधियों या संस्थाओं के प्रति) न्याय व्यावस्था अन्ततः सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास और सम्मान दोनों को भारी नुकसान पहुँचाता है ।

व्यवस्था का चुप रहना अनदेखी करना है । यह नासूर बन जाता है ।

33

न्यायपालिका
अयोध्या प्रकरण

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इतने दिनों बाद उत्तरदायित्व स्वीकार कर, खोजपूर्ण, तर्कपूर्ण, तथ्यपरक सर्वमान्य निर्णय देने से न्यायपालिका का सम्मान बढ़ा।

उसके बाद इस देश में गड़बड़ी नहीं होना एक सुखद एहसास है कि राष्ट्र परिपक्व हो गया है। अब लोकतंत्र मजबूत होगा।

कुछ बेसुरे बोल हमेशा रहते हैं।

34

अक्षम न्यायपालिका – निर्भया काण्ड

- पहले कुछ लोगों ने एक अच्छी भली लड़की का सामूहिक रेप किया, इतनी दरिन्दगी कि वह जिन्दगी मांगते-मांगते मर गयी।
- बिरले पकड़े जाने और मौत की सजा के हकदार को वर्षो बाद सजा मिली।
- 7 वर्षो तक कुछ वकीलों (नाम और पैसे के लिए) ने पूरी न्यायव्यवस्था और भारतीय जनमानस का रेप किया।
- कई घटना इससे भी भयानक होगी।
- न्याय विवेकहीन/लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए।
- हमारी न्यायिक व्यवस्था लचर है।
- न्यायव्यवस्था, जो समाज में कानून का राज स्थापित करने हेतू स्थापित है।

35

निर्भया के दोषियों को फांसी हुई,
देशवासियों को एक संतोष हुआ।
परन्तु सात साल तक न्याय भटकता रहा –
क्योंकि एक वकील ने कानून का उपयोग
न्यायालय को मदद करने के लिए नहीं किया, बल्कि कानून का दुरुपयोग किसी को (दोषी) को बचाने के लिए किया।
कानून की जगह तिकड़म अपनाये गए।
न्यायालय अपने ही नियमों में फंसा रहा गया।
एक वकील न्याय का न्यायालय का मजाक उड़ाता रहा,
न्यायाधीशों के स्व-विवेक को कानूनी जगह मिलनी चाहिए।
दोषी की मदद करने वाला भी दोषी होता है ?
फिर इसकी विवेचना क्यों नहीं होनी चाहियें ?

36

न्यायालय : 498A कानून एवं निर्णय : हम

- निर्णय अफसोसजनक, दुर्भाग्यपूर्ण एवं समाज के लिए घातक है।
- भारतीय समाज के परिवार नाम की अन्तिम संस्था को नष्ट करने वाला है।
- पति-पत्नी कभी विश्वासपूर्वक/निश्चिंतता पूर्वक नहीं रह सकते।
- बिना जांच/सुनवाई के पति पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करना न्याय की अवधारणा ही नहीं, मानवता के खिलाफ है।
- पति पक्ष की महिलाओं को यदि अकारण (बिना दोष निर्धारण के) जेल जाना पड़ता है, तो उनके, pride prestige और अधिकार के साथ घोर न्यायिक अत्याचार होता है।
- यह न्यायिक व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा करता है।

बूंदें

37

संसद और धर्म आधारित निर्णय :-

- संसद पूर्ण भारत का, भारत के समग्र नागरिकों के लिए एक रुकरूपता से नियम बनाने के लिए है ।
- अल्पसंख्यक को सुरक्षा चाहिए, परन्तु बहुसंख्यक या जनसमान्य पर हावी भी नहीं होना चाहिए ।
- कोई दो पक्ष सहमति से वर्तमान न्यायवस्था से अलग, पंच, खाप पंचायत को न्याय के लिए चुनना गलत नहीं है । लेकिन किसी भी एक पक्ष की असंतुष्टी होने पर वर्तमान, नियमन की एक ही व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे तलाक का मसला हो या अन्य ।

बूंदें

38

- पंच/काजी/न्यायपालिका का समर्थ होना, आदरणीय होना, प्रभावी होना आवश्यक आवश्यकता/अनिवार्यता है।
- न्यायपालिका का सम्मान आवश्यक एवं अपरिहार्य सामाजिक व्यवस्था है ।

बूंदें

39

न्याय : अवधारणा

हमारे देश में दुष्कर्म-रेप

रेप 'महिला'/स्त्री/लड़की/युवती का ही नहीं होता, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी परिवार, समाज या देश का होता है । रेप से जो कुछ टूटता विखरता है वह इन सबों का होता है । यह सामान्य दुर्घटना नहीं है, न यह स्त्रियों/महिलाओं का मामला है ।

बूंदें

40

सामाजिक सोच और कानून/न्याय व्यवस्था में भारी गड़बड़ है ।

- जितना कड़ा कानून उतनी ही ज्यादा घृणित, विभत्स और भयानक घटनाएँ, मनो-मस्तिक को हिलाने वाली होती है ।
  भयानक आक्रामक दरिदंगी के पीछे एक पूरा परिवेश है ।
- यदि पोर्न देखने पढ़ने की इच्छा है तो कहीं उसे कार्यान्वित करने की इच्छा जागेगी ही ।
- यदि सिनेमा में छेड़खानी करने का नतीजा 'प्राप्ति' है, तो अपरिपक्व (ज्यादातर) मन उसे बाहर कार्यान्वित करना चाहेगा ।
- समेकित निदान आवश्यक है ।
- कानून, मिडिया, समाज, न्याय व्यवस्था, जन सामान्य सभी की ईमानदारीपूर्ण सहभागिता आवश्यक है।

हमारे देश में दुष्कर्म-रेप

- दुर्घटना के ''बाद यह लोगों को बता देगी''
- 'फांसी हो जाएगा' इसलिए -
  'मार दो।'
- मार देने पर भी 'पहचाने जाने पर लोग/पुलिस जान जायेगें' इसलिए -
  'पहचानने लायक नहीं रहने दो'
- फिर भी पकड़े जाने की सम्भावना है अतः 'जला दो', 'टुकड़े-टुकड़े कर दो', प्रमाण समाप्त करने के लिए कुछ भी कर दो इत्यादि का दुष्चक्र।

दुष्कर्म-रेप

- न्याय में देरी पहला कारक है।
- न्याय प्रक्रिया की जटिलता, अकाट्य सबूत की बाध्यता, काल्पनिक आर्दशवादिता, सीधी और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था की जगह कानूनी जाल, विपरीत निर्णयों की भरमार समस्या को बढ़ा देती है।
- जज वकीलों के गलत तर्कों एवं तकनीकी कारणों से प्रभावित हो जाते हैं।

- पुलिस का समय पर काम न करना, भ्रष्टाचार, राजनैतिक, प्रशासनिक दबाव, कभी मजबूरी इत्यादि, सजा की निश्चितता को मात्र 30% की सम्भावना, बदमाशों के लिए उत्साहबर्द्धक है।
- महामारी फैलने, दुर्घटना होने पर वहाँ जाकर सम्बंधित लोग घटना स्थल पर कार्य करते है।
- न्यायपालिका, मजिस्ट्रेट भी यदि घटना स्थल पर तुरत पूरे परिवेश से स्वंय परिचित हों तो त्वरित न्याय सम्भव है। गवाह बदलने, खरीदने की सम्भावना भी कमेगी।

हमारे देश में दुष्कर्म-रेप

रेप-धमकी के विभिन्न स्वरूप शारीरिक, क्षति, के विभिन्न स्वरूप, हत्या, फिर साबूत मिटाने के लिए जलाने से लेकर कुछ भी करने की परिणति सिर्फ 'फांसी', कहीं से अपने उद्देश्य में सफल नहीं है।

सजा का स्वरूप भी चिंतनीय/विचारणीय है।

जेल में मुफ्त में भोजन, वस्त्र, आवास, और मानवीयता/भवनाधिकार के नाम पर आराम है।

रेप : -

1. महीनों, वर्षो तक साथ रहने और हर 'कार्य' में सहभागिता के बाद सिर्फ एक पक्ष पर झांसा देने, धमकी देने की दुहाई लगाना, शुरुआती समर्थन को नजरअंदाज करना भी सरासर गलत है ।
2. दूसरा (स्त्री) पक्ष भी लाभ, लोभ, चालाकी की वजह से शुरुआत कर सकती है ।
3. रेप को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है ।
4. स्त्रियां भी 18/21 वर्ष के बाद वयस्क हो जाती हैं ।
5. दुष्कर्म का अवसर प्रदान करना भी गलत है । 'गलत को गलत कहना' बहुत व्यापक है ।

हमारे देश में दुष्कर्म-रेप

- 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' 'लैगिंक समानता' के नारे सीमा से परे जाकर महौल को नकारात्मक बनाता है । जबकि लोग पैसे कमाने, नाम कमाने और चर्चा में रहने के लिए ऐसा करते/कहते हैं ।
- सेक्स के प्राकृतिक झुकाव को दानवी स्वरूप में परिवर्तित होने के कई कारक है ।
  - ❑ सिनेमा, टी0 वी0, पोर्न पत्रिका, व्यापारिक प्रचार, गलत को गलत नहीं कहने, सामाजिक बेजारी, कानूनी जंजाल इत्यादि बहुत बड़ा कारक हैं ।
  - ❑ बदला, दहशत फैलाकर गैंग बनाने, सिनेमा इत्यादि से गुर सीखकर उसे कार्यान्वित करने फिर, विधायक के रूप में प्रतिष्ठित होने की सम्भावना भी घटनाओं को अंजाम देती है ।

तलाश: रेप

- पेड़ों के जंगल और कंक्रीट के जंगल में किसकी व्यवस्था अच्छी है ।
- जंगल में रेप का, सामूहिक रेप का उदाहरण नहीं दिखता ।
- कंक्रीट के जंगल में अखवार इन खबरों से पटे रहते हैं ।
- भोजन श्रृंखला, शिकार और शिकारी का एक ऐसा सामंजस्य है जिसमें हिरण, खरगोश, भालू, मछली सभी आनुपातिक एवं प्राकृतिक रूप से आनादिकाल से जी रहे हैं ।
- जंगल में किसी के प्रति 'दास भाव' नहीं है, असली लोकतंत्र है । यहाँ दास भाव की ही प्रधानता है ।
- जंगल में भोजन, ऊर्जा-धन का संग्रह न्यूनतम है, या नहीं है ।
- अत: जंगल बचा है: जीवन बचा है ।

तलाश: रेप

- कंक्रीट के जंगल में 'संग्रह' सीमाहीन है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हर स्तर पर संग्रह ही आज की लोकतांत्रिक 'व्यवस्था' है । इसलिए काफी लोग मर रहे हैं, भूखे और नंगे हैं, दास हैं, अमानव हैं, मानवाधिकार से वंचित हैं ।
- बल के जंगल कानून का अक्सर उदाहरण देते हैं। कंक्रीट – जंगल में भी हर जगह यही तो है ।
- जंगल जीवन से ही कंक्रीट जीवन विकसित हुआ हैं, उसके नकारात्मक नियम कानून यहाँ पूर्ण विकास की ओर हैं ।
- जंगल व्यवस्था सफल है, जबतक आदमी का दखल नहीं हैं ।
- इसका सबसे बड़ा कारण जंगल में न्याय व्यवस्था, (न्यायपालिका) का नहीं होना है, न न्यायालय है, न वकील है, न डाक्टर है, न (भ्रष्ट) अधिकारी हैं, न नेता है, न विनिमय-व्यापार है, न पैसा है ।
- कितना अच्छा तंत्र है – लोकतंत्र है ।

कानून में बदलाव

कुछेक घटनाओं को आधार बनाकर हम कानून को सही स्थिति में नहीं लाकर उसे सीधा उलट देते हैं, नतीजा सम्भवत: और खराब ही होता है 498A का, SC,ST कानून इत्यादि का व्यापक दुरुपयोग इसका प्रमुख उदाहरण है।

सभी घटनाएं उजागर नहीं होती।

कई क्षम्य भी हो सकते है।

क्षणिक बहकना मानवीय एवं सुधार योग्य है।

बहक जाना दानवीय एवं दमनीय है।

कानून से पहले और ज्यादा कारगर उपाय पारिवारिक और सामाजिक अस्वीकृत है।

तलाश

कानून निर्माण एवं व्याख्या में सतुलन।

- नारी शशक्तिकरण की प्रक्रिया एक हथकण्डे के रूप में इस्तेमाल हो रही है।
- जहाँ सख्त (पुलिसबल) कार्रवाई की सम्भावना बनती है वहाँ स्त्रियों को आगे कर दिया जाता है।
- स्त्रियों द्वारा लोगों का चरित्रहनन करवाया जाता है।
- लूट, मार, अपहरण, आतंक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें स्त्री बिल्कुल नहीं होती।
- स्त्रियों द्वारा आये दिन थाने में या पुलिसबल पर सीधे हमला चप्पल, डंडे से उनकी पिटाई पूरे पुलिस तंत्र को निरर्थक करता जा रहा है। यह सामाजिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए अत्यंत घातक है।
- आतंकियों एवं अपराधियों द्वारा इसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है।
- जबकि कानून व्यवस्था के मामले में स्त्री/पुरुष बराबर होना चाहिए।
  यही स्त्रियों की मांग भी है।

तलाश

अपना-अपना कद

लोकतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय से उंचा कद प्रशांत भूषण जी का लगता है।

प्रशांत भूषण की जगह एक आम आदमी होता तो क्या उसे भी यही (एक रुपये की) सजा होती? बिरबल न्याय हो रहा है।

पहले तो उनकी चिरौरी की गयी कि यदि "आप ही ऐसा करेगें तो और लोग क्या करेगें।"

"मान जाइये सजा देने दिजिये, प्लीज!"

फिर एक रुपये के सिक्के को जिवंत कर दिया गया जो लेन देन में महत्वहीन हो चुका है।

तलाश : न्यायिक सेवा

- न्याय, कानून का राज्य स्थापित करना संवैधानिक जिम्मेवारी है।
- व्यवस्था ऐसी कि साधारण व्यक्ति की सम्पत्ति लुट ही जाती है।
- आधे का न्याय स्वयं हो जाता है क्योंकि न्यायालय में जाने की आर्थिक कूबत ही हारे हुए व्यक्ति की नहीं रहती।
- देरी और न्याय आने तक न्याय की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाए तो अलग बात है।
- हमें यह भी नहीं पता कि न्यायिक सेवा के हम उपभोक्ता (Consumer) हैं, भी की नहीं क्योंकि यदि निचली अदालत गलत है, तो आप और ऊपर जाएँ। आपकी आर्थिक औकात और ऊपर जाने की नहीं है तो चुप-चाप रहिये/सहिये/जेल हो या बेल हो।

तलाश

- न्यायालय ने यह सही चिंता जताई है कि लोगों में न्यायालय की आलोचना करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है ।
- यह अत्यंत चिन्तनीय है ।
- न्यायालय की मर्यादा अक्षुण्ण रहनी ही चाहिए।
- यह आदर भी स्वत: होना चाहिए न Command से न Demand से ।

तलाश

एक कानून है – एक निर्णय आया है ।

घूस देने वाले का भी दोष है ।

पैरवी करने वाले बेचारे एवं घुसखोर क्या करें ?

पैरवी करने वाले तो दोषी हैं ही । पैरवी सुनने वाले क्या करें ।

घूस नहीं लेने पैरवी नहीं सुन निश्पक्षता के साथ कार्य करने का बेतन थोड़े मिलता है ।

रेप करने वाले क्या करें, रूप और सेक्स की इच्छा जो है ।

मिडिया

- लोकशक्ति है ।
- लोक कल्याणकारी है ।
- राजतंत्र, साम्यवाद, अधिनायकवाद, लोकतंत्र सभी राजकीय व्यवस्थाओं में–अनिवार्य है ।
- मिडिया के बहुतों ने अपनी आहुति दी है ।
- लोगों ने अदम्य साहस, समर्पण का परिचय दिया है ।
- हमें उनका ऋणी होना चाहिए ।
- अनुशासित सामाजिक जीवन का प्रमुख कारक है ।
- गलत को गलत कहने का प्रमुख माध्यम है ।
- राजनीति और पैसा सबकुछ चौपट कर देता है ।

स्वतंत्र मिडिया

(लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ)

मिडिया पुर्णत: स्वतंत्र : कितना स्वतंत्र ?

- संविधान की धारा 19.1
- बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- धारा 19.2 restricted .....
- "in the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign State, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence."

धारा–19.2 का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है।

57

मिडिया

- हथियार के रूप में मिडिया का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है ।
- TRP के लिए वृहतर हित को नजर अंदाज करना बिलकुल गलत है ।
- मिडिया को वस्तु स्थिति सामने लाना चाहिए ।
- जाँच, निर्णय और सजा सब प्रक्रिया खुद कर लेना (MEDIA TRAIL) गलत है ।
- इसका विनियमन जरुरी है ।

58

मिडिया

परिकल्पना : जिम्मेवार एवं संवदेनशील मिडिया

हकीकत : मिडिया एक दुधारी तलवार है। अधिकांश प्रभावशाली प्रिंट मीडिया या टी०वी० चैनल विभिन्न घरानों द्वारा संचालित हैं ।

ये सभी एक लाभकारी संस्था (corporate) हैं; ईमानदार होना, निष्पक्ष होना constructive होना, राष्ट्रिय/सामाजिक हित का ध्यान रखना सम्भव ही नहीं हैं ।

- नकारात्मक समाचारों की बहुलता एवं उनकी प्रमुखता समाज में अविश्वास का निर्माण करता है ।
- लोगों में असुरक्षा की भावना भरता है ।
- दंगे फसाद फैलाने में उसकी अहम भूमिका है।

59

मिडिया

- मिडिया की आवश्यकता लोगों के विचारों, समाचारों के विनिमय/संप्रेषण के लिए है।
- आज यह एक साम्राज्य, एक शासन व्यवस्था हो गया है ।
- इनके आगे शासन (विधायिका), प्रशासन (कार्यपालिका), विशेषज्ञ (प्रोफेशनल), वैज्ञानिक, न्यायपालिका सभी नत मस्तक हैं ।

60

मिडिया का आतंक

- ❑ सभी राजनैतिक पार्टियाँ मिडिया के आगे दुम हिलाती हैं ।

या

- ❑ फिर अरबों का विज्ञापन रूपी हथियार से मिडिया को सर्कस कराते हैं ।
- ❑ दोनों ही स्थिति में मिडिया लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है ।
- ❑ स्वतंत्र मिडिया की रक्षा करना एवं अनियंत्रित स्वतंत्र मिडिया से अपनी/राष्ट्र की रक्षा करना आवश्यक है ।

बूंदें

61

मीडिया का उत्तरदायित्व

- न देश के प्रति
- न समाजिक मूल्यों के प्रति है ।
- न संवेदन शीलता है ।
- न आत्म नियंत्रण है ।
- सिर्फ व्यापार के प्रति वफादारी है ।
- उद्देश्य की गम्भीरता नहीं, सिर्फ स्पर्धा है ।
- उत्तरदायित्व पूर्ण मिडिया देश के लिए, जनतंत्र के लिए आश्यक है/अनिवार्य है ।

बूंदें

62

सिनेमा

- सिनेमा सेंसर को नकारता है।
  सड़ी गली एकाकी घटनाओं का नाटकीय वर्णन कर लोगों को सेक्स, रेप, मर्डर, हिंसा, डकैती इत्यादि के नये नये गुर सिखाता है । इसके लिए मानसिकता और वातावरण बनाता है ।
- इसको 'सृजनात्मकता' कहता है ।
- नग्नता प्रदर्शन, शारीरिक चेष्टाओं से गलत प्रचलन, बहुत सारी बुराईयों को जन्म देने वाले मूल कारण हैं ।
- इसके दुश्प्रभावों को कानून से रोकने की कोशिश नाकाम है ।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने लिए सिर्फ पैसा कमाने का साधन बनाता है ।

बूंदें

63

मिडिया का उत्तरदायित्व : सिनेमा

- समान्य में, अच्छाई में इनकी रुचि होती नहीं, 'असमान्य' ही इनका विषय होता है ।
- बहुत सारें सिनेमा अत्यन्त सोद्देश्य होते हैं, अच्छे संदेश (message) से परिपूर्ण होते हैं । कड़वी सामाजिक सच्चाईयों को उजागर करते हैं ।
- स्वस्थ्य मनोरंजन देते हैं ।
- स्वस्थ्य संदेश (message) देते है ।
- अपने संस्कारों एवं परम्पराओं की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है ।
- टी० वी० चैनल सड़े गले समाचारों को दिन भर और अत्यंत नाटकीय ढंग से अनावश्यक रूप से प्रसारित करता रहता है ।

बूंदें

64

मिडिया :

- उत्तरदायित्व बोध न्यूनतम है । खासकर electronic media का ।
- एक 'power' बनने और उसे भुनाने की ललक है ।
- सारी वुद्धिमत्ता का उपयोग अपनी छवि एवं चैनल की रेटिंग बढ़ाने का होता है ।
- राष्ट्रीय किसी भी घटना का दोहन अपने हित में करता है, चाहे देश का कितना भी अहित हो ।
- पक्षकार के रूप में बंट जाते है ।
  खोज-खोज कर सभी सम्भावनाओं को अपनी कमजोरियों प्रसारित कर दुश्मनों को फायदा देते है ।
  इसे जानने का हक कहते है ।

मिडिया :

- जानने का हक और जानने की जरुरत में फर्क करना होगा ।
- कोई भी (सांसद या न्यायपालिका या कार्यपालिका) पूर्ण स्वतंत्र नहीं है ।
- मिडिया का भी बिना शर्त, पूर्ण स्वतंत्र होना देश/समाज के लिए अत्यन्त घातक है ।
- संविधान की धारा 19.2 को सही ढंग से लागू करना आवश्यक है ।

मिडिया :

जो मिडिया "किसी का" है वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है ?

जो मिडिया सरकार से, किसी पक्ष से Advertisement के लिए/आर्थिक लाभ के लिए लालायित है; आर्थिक लाभ के लिए ही स्थापित है; वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है ?

यदि पक्षपात समाचार, लेख, विश्लेषण की शक्ल में हो तो मिडिया नकारात्मक/घातक हो जाता है ।

मिडिया की स्वतंत्रता, इसकी निष्पक्षता स्थापित करना हमारा कर्तव्य है ।

मिडिया

- एंकर बहुत बड़े तीसमार खाँ हो जाते हैं ।
- ब्रह्माण्ड के सभी सामान्य, विशिष्ट, अतिविशिष्ट विशेषज्ञता पर अपनी राय रखते हैं, इसमें कोई बुराई या गलत नहीं है, परन्तु उसे इस रूप में प्रसारण करना कि यह अन्तिम सत्य है, गलत है, हानिकारक है ।
- इनकी साधारण बुद्धि के आगे सभी विशेषज्ञताएँ समाप्त हो जाती हैं ।
- ये सबसे सवाल पूछ सकते हैं इनसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता है ।

मिडिया

- अपनी व्यक्तिगत राय को वैश्विक/सर्वमान्य राय के रूप में पेश करते हैं ।
- इनके तर्क, कुतर्क, कठतर्क सभी प्रसारण के योग्य होते हैं – उसमें न प्रतिवाद सम्भव है न मतांतर (counterpoint).
- जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र किसी भी विभाजित करने वाले आधार को खूब उधेड़-उधेड़ कर समाज, देश को आहत/एवं अहित करते है । इनकी उपयोगिता/दुरूपयोग को संतुलित करना एकदम जरुरी है या Mass media के स्वरूप को बदलना आवश्यक है ।

मिडिया

कभी-कभी इनका statement होता है, जिसमें उनका पूर्वाग्रह स्पष्ट से भी ज्यादा उजागर रहता हैं।

तर्क, खोज या प्रमाण/का सामान्यत: अभाव रहता है । बस इनको एक मौका होता है, बोलते रहते है ।

अधिकार सम्पन्न, मिडिया के खौफ से/ उससे लाभ लोभ से कुछ नहीं कहते, बोलते, अन्य हमलोग तो सिर्फ कान रखते हैं । हमारे पास अभिव्यक्ति का/इनके दुर्व्यवहार के प्रतिकार का कोई उपाय नहीं होता ।

आवश्यक अनुशासन एवं आत्मानुशासन के साथ स्वतंत्रता मूल मंत्र है ।

मिडिया

- मिडिया द्वारा घटना/समस्या का अतिकरण खतरनाक है ।
- 'लघुकरण' और 'अतिकरण' करने की क्षमता इन्हें राजनीति में दखलदांजी करने का मौका दे देता है ।
- पीत-पत्रकारिता, मिडिया ट्रायल होने लगता है।
- निराकरण; आत्मबोध या 'किसी' के प्रति जबावादेही आवश्यक है।

चिंतन

दलगत राजनीति : सरकार का निर्माण

संवैधानिक प्रश्न है: -

चुनाव आयोग किसे विजयी घोषित करती है, सिर्फ व्यक्ति को या पार्टी को ?

व्यक्ति का पार्टी से या पार्टी का गठबंधन से बंधन का कानूनी स्वरूप क्या है ।

जब गठबंधन चुनाव के पहले घोषित/ लिखित है तो बाद में यह वाध्यकारी कैसे नहीं है ।

इसको Implement करने का क्या उपाय है/हो सकता है ?

एक वोट से दो निर्णय लेना मूलत: गलत है इसकी कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है ।

- एक वोट से एक निर्णय की व्यवस्था करनी होगी ।

पार्टी या गठबंधन के वैधानिक प्रावधान बनाने होगें ।

चितंन

1. दलगत राजनीति : गठबंधन

न आचार का, न विचार का सिर्फ अवसरवाद का, बिना पेंदें का लोटा है ।

जब मर्जी टूटता है ।

जब मर्जी जुटता है ।

नीति विहीन है, चरीत्र से हीन है ।

लचर है ।

न कोई सबंध है, न कोई बंधन है ।

कुर्सी की ही गांठ है, सिद्धांत तो बेइमानी है ।

जिसे निश्चित रूप से नहीं चुना उस की सरकार है ।

गठबंधन सरकार है ।

जनमत का क्या दरकार है ?

73

दलगत राजनीति – सरकार निर्माण और जनमत

एक उदाहरण महाराष्ट्र – 2019 चुनाव

- महाराष्ट्र के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया फिर भी सरकार तुरंत नहीं बनी – दलगत राजनीति के कारण ।
- एक कनीय पार्टी कम सीट लाकर भी बहुमत एवं जनमत का हाथ उमेठता रहा ।
- एक राज्य में एक बार एक निर्दलीय व्यक्ति अपनी स्थिति का लाभ उठाकर मुख्यमंत्री बन गया अरबों – खरबों का घोटाला हुआ ।
- हम सब क्या कर पा रहे हैं, क्या कर पाए थे, आगे भी इसी प्रकार हमारा वोट मजाक मात्र रहेगा – दलों के कारण ही तो !

74

दलगत राजनिति – सरकार निर्माण और जनमत

किसी पार्टी के नेता का पुत्र/पत्नी होने के कारण C.M./P.M. बन जाता है जिसको जनता का कोई समर्थन नहीं होता ।

- उचित लगता है ? लोकतांत्रिक है ?

ऐसी गलत अलोकतांत्रिक सम्भावना बनती है, सिर्फ दलगत राजनिति के कारण ।

पहले भी कई राज्यों में (बिहार में भी) ऐसी स्थिति हो चुकी है ।

75

दलगत राजनीति पर हम लिख चुके हैं । महाराष्ट्र में चुनाव एक सरकार के निर्माण का उदाहरण हमारी मान्यताओं का वास्तविकताओं का सीधा और स्पष्ट प्रमाण है।

76

दलगत राजनिति : सरकार निर्माण और जनमत

महाराष्ट्र में सरकार बनने के नियामक (घटक) :

BJP, Shivsena, NCP और Congress पार्टी;

न चुनाव आयोग, जिसने कुछ गठबंधनों पर चुनाव लड़वाये, न महाराष्ट्र की जनता ।

महाराष्ट्र, की जनता अब सिर्फ मुंह ताक रही है ।

कोई संवैधानिक व्यवस्था कारगर नहीं है कि जब प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं तो सरकार क्यों नहीं बनेगी ।

प्रतिनिधि चुन लिए जाने के बाद भी सरकार का निर्माण नहीं होना संवैधानिक विफलता और संकट है । दलगत राजनीति के कारण ही तो !

77

दलगत राजनीति : सरकार निर्माण और जनमत

कई बार सरकार निर्माण हमारे संविधान एवं इसके रखवाले की भयानक विफलता के रूप में सामने आई है ।

लोकतंत्र के लिए CRISIS है।

- यह स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान होना ही चाहिए कि आम जनता व्यक्ति को चुनती है ।
- यह घोर अनैतिक, असंवैधानिक, अलोक-तांत्रिक है कि वोट पार्टी/गठबंधन के नाम पर लिए जाएँ और बाद में समीकरण बदल दिए जाएँ ।
- जन प्रतिनिधि को झुण्ड में होटलों में बंधकों (भेड़ों) की तरह पार्टी के नेता के गुलामों की तरह रखा जाना जनतंत्र कैसे हो सकता है?
- जनता ने पार्टी के चीफ को वोट न देकर हर अलग-अलग व्यक्ति को दिया था। पार्टी किसी की (नेता की) नीजी सम्पति नहीं होती।

अपनी सरकार का निर्माण करें ।

सामूहिक सोच का निर्माण करें !!

78

दलगत राजनीति

- महाराष्ट्र के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार निर्माण में जनता के मत से कोई सामंजस्य नहीं है ।
- चुनाव पूर्व समीकरण से अलग कोई भी सरकार पुर्णत: असंवैधानिक, है, गैंगतंत्र है ।
- सविधान के रखवाले संरक्षक को स्वत: संज्ञान लेकर इसपर राष्ट्रहित में, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए था ।

एक प्रभावी, दूरगामी, देश हित में निर्णय/आदेश पारित करना चाहिए था ।

दल-बदल, खरीद-फरोख्त से अच्छा है राष्ट्रपति शासन/समयानुसार पुन: चुनाव करने में भी कोई हर्ज नहीं है ।

सामूहिक सोच का निर्माण करें !!

79

दलगत राजनीति :

सरकार निर्माण : जनमत

- न जनता (का मत)
- न चुनाव आयोग का (जिनके तहत चुनाव कराये गए)
- न संविधान रक्षक-न्यायपालिका एवं विधायिका का कोई महत्व है।
- सत्ता (नहीं पैसे) का ऐसा बन्दर-बाँट और सभी निर्णायक घटकों का प्रभावहीन रहना अत्यंत घातक है ।

जनतंत्र मर रहा है ।

सामूहिक सोच का निर्माण आवश्यक है ।

80

दलगत राजनीति : सरकार निर्माण

जन सामान्य के लिए सन्देश ?

1. किसी भी तरह हो सत्ता पद/लूटो ।
2. नैतिकता, नियम, रिती-रिवाज (न्याय-पालिका भी) बातें है बातों का क्या ?
3. यह सब कमजोर और जन सामान्य के लिए है।
4. कोई देखने वाला नहीं है ।
5. एक अलग शासक वर्ग बन चुका है ।
6. जन साधारण से उसका कोई सरोकार नहीं है।
7. ऐसी घेराबंदी बना दी गयी है कि उसमें उत्तम व्यक्ति, नौकरी पेशा, इंजिनियर, डॉक्टर इत्यादि नहीं जा सकते, वकील, शिक्षक, व्यवसाय अन्य कोई रोजगारवाले पहले इस्तिफा नहीं देते और सत्ता का खूब दोहन करते हैं।
8. यदि हम नहीं चेते तो अनर्थ अवश्यम्भावी है ।

81

दलगत राजनीति : बंद/धरना/रैली

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक माखौल बन गया है एवं उसकी भावना के प्रतिकूल है।

संभ्रातों का चुप रहना अपराधिक है ।

अराजकता, आतंकवाद में परिवर्तित हो गया है ।

'बंद'करवाने की शक्ति आतंक फैलाने की शक्ति है, इसे कोई स्वीकार नहीं करता ।

'बंद'/धरना आदि दलगत-राजनीति, अशिक्षा, बेरोजगारी, नेता बनने की मिली-जुली अभिव्यक्ति है ।

जो कानून 2014 तक आ चुके शरणार्थियों के लिए है, जो बहुत बड़ी संख्या में भी नहीं हैं उनके लिए है, फिर इसे धर्म/संविधान के उलट मानना सिर्फ जबर्दस्ती है ।

एक शस्त्र की तरह दूसरे को चुप कराने का उपाय है।

82

दलगत राजनीति : CAA, NCR

मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिसके पास अपने नागरिकों की सूचि नहीं होगी ।

नागरिकता सूचि के बिना किसी को कानूनी, संवैधानिक अधिकार, आर्थिक सुबिधायें इत्यादि का क्या आधार हो सकता है ?

83

दलगत राजनीति : CAA, NCR

पहले से ही अत्याधिक घनत्व वाले (person/sq.km. जो भारत में चीन से लगभग तीन गुना ज्यादा है), इस देश में जब भी कोई बसता है तो सिर्फ वास्तविक (Bonafide) नागरिक की रोजी-रोटी छीनता है, उसकी जमीन कब्जा करता है, उसी के आर्थिक वजूद का बटवारा होता है ।

अपने को स्थापित करने के लिए ये घुसपैठिये हर प्रकार से वास्तविक (Bonafide) नागरिको के साथ के कुकर्म, आतंक, सामूहिक कत्लेआम, लूट मार कुछ भी करते हैं । इनका समर्थन देने वाले नेता कभी कोई तर्क, कोई आधार नहीं देते सिर्फ कहते हैं केन्द्रीय कानून को नहीं मानेगें । ऐसा कहना/करना कैसे संवैधानिक है ।

भारतीय नागरिको की कीमत पर विदेशियों की मद्द ज्यादा एवं जल्दी करना कैसे देश द्रोह नहीं है । सत्ता में रहने वाले जल्दी देशद्रोही हो सकते हैं।

84

दलगत राजनीति : CAA, NCR

जब दोनों सदनों में सभी को अपनी बातें रखने का मौका मिला, फिर पास हुआ तो इसे राजनैतिक दलों द्वारा नकारने से बड़ा असंवैधानिक बात और क्या हो सकता है/इन्हें पुन: Media के मंच पर सत्ता पक्ष के साथ समय मिलना चाहिए और बिना आधार /तर्क/सबूत के दिए गए वक्तव्यों के कारण हुई हिंसा और क्षति के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए त्वरित सजा मिलनी चहिये ।

अराजकता फैलाने वाले लोग प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं । क्योंकि इनके पास एक दल है; सीधा-सीधा गैंग है । जिसकी जिह्वा सिर्फ सत्ता के लिए लपलपा रही है, चाहे वो देश विभाजन कर हो या इसे जलाकर हो ।

बूंदें

85

दलगत राजनीति

- सामूहिक प्रगति में सबकी प्रगति सुनिश्चित है।
- 'सामूहिक सोच' दिशा निर्धारण के लिए आवश्यक है।
- संकल्पित हों, अन्यथा 'कुछ लोग' सामूहिक हित को नष्ट कर देंगें।
- केरल विधानसभा में CAA के बिरुद्ध प्रस्ताव पारित करना भारतीय संघीय व्यवस्था को खुली चुनौती है।
- कल बंगाल में भी ऐसा ही होगा–हुआ।
- इसका कारण व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा और दलगत दुश्मनी है।
- ऐसा सिर्फ दलगत राजनीति के कारण हुआ है।

आप भी सोचें और निर्णय लें।

बूंदें

86

तलाश

दलगत राजनीति : जातिगत राजनीति

- ❑ दलदल की विशेषता है: निकलने की जितनी कोशिश उतनी ही मुश्किल।
  पिछले बिहार चुनाव का सवक।
- ❑ सभी दलों के टिकट का मुख्य आधार जाति/धर्म।
- ❑ मंत्रिमंडल निर्माण का आधार जातीय समीकरण।
- ❑ विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव जातीय संतुलन (जैसा मिडिया से आम जन को समझ में आता है।)
- ❑ जातिगत व्यवस्था या उसका विचार और गहरे और गहरे जड़ें जमा रहा है।
- ❑ सामाजिक जीवन में सरकार या अन्य एजेसिंयों के कार्य में एक बड़ा कारक है जाति।
- ❑ लेकिन कहते हैं जातीयता गलत है।

बूंदें

87

आजादी

आजादी, स्वावलम्बन एवं संप्रभुता, राष्ट्रीय (सामूहिक) जीवन का आदर्श एवं उद्देश्य है।

ये बहुत मूल्यवान (मंहगे) हैं।

इसके लिए बहुत मूल्य (रक्त भी) चुकाना पड़ता है। (चुकाना पड़ा है)

'स्वशासन', शासित होने से बहुत ज्यादा कठिन हैं।

ये तभी मिल सकते हैं जब आप दूसरों के लिए भी इसे सुनिश्चित करें।

सिर्फ अपने लिए आजादी/सम्प्रभुता सम्भव नहीं है।

बूंदें

88

आजादी

आजादी, अभिव्यक्ति, हिंसा; इसकी परिभाषा (समझ) सुनिश्चित करनी पड़ेगी।

सभी चीजों की सीमा भौगोलिक हो या आभासीये, दूसरे की सीमा से सटी होती हैं।

हर क्षेत्र की चौहद्दी होती है।

अपनी चौहद्दी के अन्दर आप स्वतंत्र हैं।

उसके बाहर तो नहीं।

देश/समाज को नुकसान पहुँचाने वाली सभी अभिव्यक्तियों का/प्रमाण/जिम्मेवारी होनी चाहिए।

89

आजादी

आजादी और अराजकता में फर्क तो करना पड़ेगा।

अपनी राजनैतिक लिप्सा/महत्वाकांक्षा के लिए बिना सीमा की आजादी और बिना सबूत/आधार/अंर्तनिर्हित तर्क/उद्देश्य के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ दूसरे की आजादी का हनन है। चाहे देश ही दांव पर हो, हर कोई नहीं बोल सकता है, न उसे अवसर है, न उपाय। दल/गैंग के लिए कोई रोक नहीं है।

90

आजादी

इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर वे देश की प्रगति, स्वतंत्रता, एकता, को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं

अत: देशद्रोही बातों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा में भी फर्क करना आवश्यक हो गया है। निरपेक्ष, निस्वार्थ, बुद्धिजीवियों का सुविधाभोग से निकलकर सामूहिक आवाज बुलंद करना आवश्यक हैं।

एक नियामक संस्था का रूप लेना चाहिए।

91

संकट

संवैधानिक संकट/राष्ट्रीय संकट

केन्द्र (संसद) के फैसले के विरुद्ध केरल विधान सभा फैसला लेती है ऐसा ही अन्य राज्य करते हैं।

पंचायत स्तर पर भी संसद के फैसले की समीक्षा होगी।

संसद के मायने ?

न्यायपालिका का रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य पर निर्णय सुनाना और उसका हर ऐसी छोटी-छोटी बातों में संलिप्त रहना लोकतंत्र के प्रमुख तंत्र की विफलता का सीधा प्रमाण/उपज है।

92

संकट: मिडिया

राष्ट्रीय संकट में भी मिडिया का उचित-अनुचित का ध्यान न रखना और न्यायपालिका की तरह अपने को संप्रभु मानना भी एक बड़े संकट को जन्म दे चुका है।

हर राजनीतिज्ञ और राजनैतिक दलों का सिर्फ वोट बैंक के अनुसार ढलने एवं निर्णय की मजबूरी (दलगत राजनीति के कारण) एक अप्रत्याशित राष्ट्रीय संकट उपस्थापित कर चुका है।

93

संकट

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी प्रकार की कोई मर्यादा का पालन नहीं, कुतर्को के सहारे नहीं पचने वाली बात और भाषा एक अलग आसन्न राष्ट्रीय संकट है; क्योंकि हर कोई और नीचे जाने में कोई संकोच नहीं कर रहा है।

जनता का राष्ट्रीय और सामूहिक हित की बात छोड़कर, मुफ्त का टी० वी०, मुफ्त का बस में सफर, यह और वह मुफ्त (कहाँ से ?) वोट की वेदी पर सबकुछ कुर्वान करना भी बहुत बड़ा संकट है ।

94

संकट

हर घर से अफजल पैदा होगा (अफजल ने किसी व्यक्ति पर नहीं संसद पर हमला किया था) भारत तेरे टुकडे होंगे, के फड़कते नारों के बल पर राष्ट्रीय पार्टियों में मान एवं स्थान पाना और उसे इसी बात के लिए तरजीह देना कि 'हिम्मती' है एक संकट ही हैं ।

हमारी बनायी संस्थाएँ जब विफल हो रही है/हो चुकी है हमें ही नयी संस्थाएँ, तरीके, मानक और आदर्श स्थापित करने होंगे ।

क्रमशः

95

संकट

अयोध्या मामले में असली समाधान सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, दोनों पक्षों की परिपक्वता है ।

कितना सुकून है !

370 हटाये जाने की सफलता जनता की परिपक्वता के साथ अवांछनीय तत्वों का सलाखों के पीछे होना और फौलादी इरादा दोनों है ।

देश के लिये अत्यावश्यक CAA, NCR की सफलता भी इन्हीं बातों पर निर्भर करता है ।

मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस देश के निवासियों (हिन्दू/मूसलमान/किसी) में कोई ..... .भेद भाव करने की सामर्थ्य रखता है, या यह सम्भव है या करना चाहता है, कल्पना में भी ऐसा सोचना सिर्फ गलत सोच है ।

सोच की ही वेइमानी/खराबी है ।

क्रमशः

96

संकट

16 से 20% कभी भी व्यवहारिक रूप से अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है –

क्योंकि शायद ही किसी अन्य तबके की संख्या इससे ज्यादा है । (जाति है, अगड़ी और पिछड़ी है, SC और ST है ।) यह वर्गीकरण सभी भारतियों को समरस होने से रोकता है ।

धर्म/और राजनैतिक पार्टी के ठेकेदार, वस्तुतः धर्म की सियासत करने वाले, अपनी गद्दी की सम्भावना देखते हैं ।

उन्हें चिन्हित एवं दण्डित करना आवश्यक है।

तोड़ने वालों में तो मुसलमानों से ज्यादा हिन्दू हैं।

मुझे अफसोस है एवं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हिन्दू/मुसलमान की बात की । तलाश में सभी एक जैसे-माननीय एवं प्रिय देशवासी हैं ।

बाहरी देश/ताकतें हमें आर्थिक, सामरिक रूप से कमजोर रखना चाहते हैं; अतः आंतरिक मामलों में बयान देते है ।

हमें संप्रभु होने के लिए आर्थिक/सामाजिक मजबूती चाहिए ।

97

अन्यान्य

हम और आप

समझ से परे : प्रदूषण

1. दिवाली में पटाखें न चलायें यह सुरक्षा के लिए अच्छा, आवश्यक और सराहनीय सन्देश है ।
2. स्कूलों में बच्चों को say 'No' to cracker, लेकिन बड़ों के सभी उत्सव वाले मौको पर, ओलम्पिक हो या राष्ट्रीय उत्सव खूब आतिशबाजी होती है । और उनका मनमोहक दृश्य टी० वी० इत्यादि माध्यमों से खूब प्रचारित किया जाता है ।

98

समझ से परे : प्रदूषण

I. दिवाली में, हर प्रकार के आयोजनों में होने वाली आतिशबाजी से, दिनरात धुएं निकलने वाली चिमनियों से, लाखों AC के चलने से, गाड़ियों एवं मशीनों में पेट्रोलियम जलाने से प्रदूषण नहीं फैलता ? इनपर रोक नहीं लगती।

II. शहरों में नालों की सफाई एवं कूड़ा कर्कट के मैनेजमेंट पर अरबों रुपये सरकार खर्च करती है ।

III. मजबूर और कमजोर किसानों पर पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाती है और उन पर दण्डात्मक कार्रवाई की बात करती है । उसका जिम्मा नहीं लेती ।

99

किसान अभी भी गुलाम हैं ।

- किसान, स्वास्थ्य सेवा से कोसों दूर परन्तु 'स्वास्थ्य कर' देते हैं ।
- शहरी लोग कोई स्वास्थ्य टैक्स नहीं देते, उन्हें हर स्तर की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है ।
- नौकरी-पेशा लोग, समर्थ एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ उठाने की स्थिति में रहने के बाद स्वास्थ्य भत्ता पाते है ।
- किसान हर स्तर की शिक्षा से कोसों दूर, 'शिक्षा कर' देते हैं |
- शहरी लोगों को हर स्तर की शिक्षा सुलभ, परन्तु कोई 'कर' नहीं–कई नौकरी-पेशा को बच्चों की शिक्षा के लिए Donation तक देने का प्रावधान है । city allowance भी मिलता है ।

100

किसान अभी भी गुलाम हैं ।

- सभी प्रकार के सभी स्तर के उत्पादक अपने उत्पाद का दाम स्वयं तय करते हैं । किसान अपने उत्पाद का दाम तय करने में असमर्थ हैं और सरकार उनका Minimum Price तय करती है ।
- उद्योगों को सस्ती बिजली, किसानो से जबर्दस्ती हासिल जमीन, मुफ्त में सड़क एवं अन्य Infrastructure देती है, टैक्स कन्सेसन देती है उनके लिए Industrial area, Special economic zone पर अरबों खर्च करती है किसानों को ? diesel subsidy, seed subsidy का नाटक । उनके दोहन का उपाय है।

101

❑ किसान एक तरफ अंतिम उपभोक्ता (consumer) हैं, वह हर प्रकार एवं सभी स्तर के मुनाफों और भ्रष्टाचार का मूल्य चुकाता है, दूसरी तरफ अपना उत्पाद न्यूनतम मूल्य पर बेचता है जिसे विभिन्न स्तर के व्यापारी जायज नाजायज जमाखोरी/संग्रह इत्यादि द्वारा कई गुना लाभ कमाकर उपभोक्ता को पहुँचाते हैं।

102

अन्यान्य/विचारणीय

कोरोना प्रभाव !

- जो लोग उँगलियों पर परमाणु बटन रख दुनिया को दहशत में रखते हैं, अपने कमरों में बंद हो गये।
- वसुधैव कुटुम्बकम् की तर्ज पर पूरे विश्व को अपना मानते हुये विचरण कर रहा है।
- अदृश्य, निरपेक्षय ''सब एक ही हो'' का पाठ पढ़ा रहा है।
- कोई मतभेद, कोई मतांतर, कोई सीमा रेखा नहीं, न राजनैतिक, न धार्मिक, न वैचारिक, न साम्यबाद/सम्राज्यबाद/फासीबाद-सभी से ऊपर।
- अपने पराये की पहचान भी समाप्त कर रहा है।
- आदमी के अहंकार को उसकी औकात दिखा रहा है।
- सिरिया, इजरायल युद्ध से ज्यादा असरदार।
- आतंकबाद से बड़ा आतंक।

103

कोरोना प्रभाव !

मान्यताओं/विश्वासों से ऊपर विज्ञान और तर्क में विश्वास कायम करने में सक्षम।
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, देवालय, पूजा स्थल सब बंद।
भोज बंद, शादी/अन्य सम्मारोह बंद।
रिश्तेदारियाँ बंद,
होटल बंद, यतायात बंद।
स्कूल बंद, कॉलेज बंद, फैक्टरी बंद,
कार्यालय बंद, कानून और न्याय भी बंद,
सब घर के अन्दर, केवल कोरोना ही बाहर-
शासन, प्रशासन भी बंद,
सिर्फ कोरोना का ही शासन है।
कोरोना का सन्देश बिलकुल स्पष्ट है।
दुनिया के लोग (आदम जात), सभी भेद मिटाकर एक हो जाओ।
तुम्हारी (आदम जात की) लड़ाई एक दूसरे से नहीं;
दूसरे जीवन स्वरूप से होने वाली है।

104

तलाश

कोरोना

मानव शरीर विचारों का एक instrument है।
युद्ध शरीर का नहीं विचारों का होता है।
द्वितीय विश्वयुद्ध नस्ल-वाद और उसके लिए दूसरों का संहार, लोगों पर अपनी महत्वाकांक्षा थोपने के विरुद्ध था।
विजेता विजित के यहाँ जमे नहीं रहे। अपनी-अपनी जगह लौट गए।
कोरोना की खोज, इसका इस्तमाल कर मानव (देश) को मजबूर कर उसका आर्थिक दोहन एवं पृथ्वी के भूगोल पर कब्जा, लोगों को अपने आगे शीश झुकाने के लिए मजबूर करने की मंशा से हुआ। कितना घृणित, मानवता के विरुद्ध कितना भयावह षडयंत्र।

तलाश- एक आन्दोलन : विचारणीय

- कितना स्पष्ट है कि चीन हर तरफ से हमें घेर रहा है फिर भी हम चीनी सामान खरीद रहे है – देशद्रोह ही है ।
- लाभ के लिए गुणवत्ता नहीं देना (जो हमारे सरकारी और गैर सरकारी उत्पादक कर रहे हैं) भी देशद्रोह ही है ।
- सैन्य शिक्षा, तकनीक श्रेष्ठता आर्थिक प्रभुता ही हमें गुलामी से बचा सकता है ।
- गुलामी बहुत कष्टकर है ।
- (स्वर्णमंदिर अमृतसर का म्यूजियम दर्शनीय है ।)

भारत रत्न

कुछ रत्न को धारण कर रत्न को महत्वपूर्ण बना देते हैं ।

कुछ उस रत्न को धारण कर महत्वपूर्ण होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से रत्न की चमक कम हो जाती है ।

रत्न तो बिरले होते हैं । वहुतायत होने से रत्न की महिमा स्वत: घट जाती है ।

इसी वजह से वह सही व्यक्ति के पास हमेशा नहीं पहुँच पाती है ।

भारत में आज एक व्यक्ति ने अपने कर्म से भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार किया है । योग का digitalization कर दिया है ।

देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता को भी ऊँची श्रेणी में पहुंचाया है ।

विल्कुल अलग क्षेत्र उत्पादन और वाणिज्य में भी चमत्कार दिखाया है ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक गुणात्मक और बिल्कुल खास पहल की । सब कुछ सिर्फ देश के लिए ।

इस रत्न की पहचान भारत रत्न की बौछार करने वाले को नहीं है ।

तलाश : देश का असली दोष

- राष्ट्रपति पुतिन एवं राष्ट्रपति ट्रम्प सीधी कुश्ती कर फैसला क्यों नहीं कर लेते ?
- राष्ट्राध्यक्ष शी० जिन पिंग और मा० प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भी ढिशुंग-ढिशुंग कर फैसला कर लेते ।
- औरों की बात मैं नहीं जानता परन्तु मेरे परमदरणीय नरेन्द्र मोदी जी तो बिल्कुल पिट जायेगें क्योंकि जब भी सीधी लड़ाई होगी, यहाँ एक वाम पंथ होगा जो नरेन्द्र मोदी का वायां हाथ पकड़े रहेगा, एक दक्षिण पंथ होगा जो उनका दायां हाथ मजबूती से पकड़ेगा । एक भारत टुकड़े-टुकड़े गैंग होगा जो उनका एक पैर पकड़ेगा और दूसरा कटट्रवादी, आंतकवादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले । वेचारे मोदी कबतक सर धुनेगें। जिन पिंग का हाथ पैर सबकुछ स्वतंत्र होगा, पूरा शरीर चुस्त और दुरुस्त और एक होगा ।
- यदा-यदा ही धर्मस्य.....

तलाश

भारत में असली जनतंत्र है ।
कहीं कोई दबाव कोई बंधन नहीं।
मन है तो चिकित्सक अस्पताल आयें ।
मन हो और यदि खुद आता हो तो शिक्षक स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाये-अन्यथा ट्यूशन करें, कोचिंग करें। मन हो तो विधार्थी आयें और पढ़े अथवा कोचिंग करें । मस्ती करें । राजनीति के दाव आजमायें ।
अभियंता भी कुछ 'अतिरिक्त' के लिए करें, अथवा 6 माह का कार्य 6 साल में होगा – 100 रु० का काम 1000 में होगा ।
लिपिक वर्ग तो असली शासक है, उनके अनुभव, हथकंडे और तरीके हैं ।
चर्तुथ वर्ग के हाथों में झण्डे हैं। मुंह में नारे हैं ।
कुछ तो शासक हैं । निर्णय इनके ऊपर वाले लें, कार्य इनके नीचे वाले करें ।
नेता पहले कुर्सी पर काबिज तो हों, और उसपर उनकी अनवरत पकड़ और स्थिरता तो हो जाये फिर... ... करेगें ।

भारत में भगवान का निवास हैं ।

तलाश

- अपने शरीर के मालिक और उपभोक्ता हम हैं अतः इसका, हर अंग स्वस्थ्य और सही कार्य कर रहा है 'हमें' ही देखना है।
- भारतीय संसद की इतनी भद्द कभी नहीं हुई। संसद के अन्दर कुछ भी चलेगा, सीमाहीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी, परन्तु बाहर तो संसद ही चलेगा अन्यथा यह है ही क्यों ?
- ❑ भारत में राज्यों का ढीला ढाला ऐच्छिक Federationn नहीं है। एक सशक्त केन्द्र है। अखण्ड है।
- ❑ देश की सम्प्रभुता, सुरक्षा के आगे और कोई 'आजादी' नहीं होती।
- ❑ आज संसद के कानून को केरल में, बंगाल में अमान्य करते हैं ऐसा कैसे सम्भव है। (Concurrent) समवर्ती विषय अलग है।
- ❑ वह दिन दूर नहीं जब एक जिला पर्षद एक पंचायत, संसद के किसी कानून को अमान्य करने लगेगा।
- ❑ कड़े कदम भारतीय संघ के जिन्दा रहने के लिए आवश्यक है।
  'हमे चाहिए आजादी' अभिव्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता के टुकड़े-टुकड़े करना आवश्यक है।

तलाश : लोकतंत्र की तलाश

- U.S.S.R. में साम्यवाद था - मिखाइल गोर्वाचेव के शासनकाल में 'ग्लास्नोस्त' में उदारवाद/ लोकतंत्र की वयार चली U.S.S.R. खण्डित-खण्डित हो गया।
- आज पुतिन के शासनकाल में उनके धुर विरोधी को बिष दिया गया।
- चीन में साम्यवाद ? पिछली दो (2) पीढ़ी से आर्थिक उवारवाद (लोकतंत्र ?)
- ❑ पूरे विश्व के धानिकों में चीन अग्रणी है।
- ❑ शी जिन पिंग के शासनकाल में दुनिया को कोरोना का उपहार - उसे छुपाना कमतर आकना। दुनिया को सावधान करने वाला चिकित्सक गायब।
  दुनिया के संकट पर खूब कमाई करना साम्यवाद है न !
- ❑ जैक मा० (अलीबाबा) का सरकार विरोधी हल्का सा रुख और विश्वपटल से गायब हो गए।

तलाश : लोकतंत्र की तलाश

- लोकतंत्र का **ICON, USA** में संसद का ही घेराव हो गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नए राष्ट्रपति की घोषणा रुक गयी।
- तथाकथित किसान आन्दोलन ने भारतीय लोकत्रंत को बंधक बना रखा है। यहाँ की तो बात ही नहीं, शाहीन बाग हो, ममता बनर्जी का बंगाल हो, राजनैतिक पार्टी हो, बाहुबली हो लोकतंत्र कुछ लोगों के जूते की नोक पर!

क्रमशः

तलाश : लोकतंत्र की तलाश

- 'लोकतंत्र' पर गहन पुर्नविचार आवश्यक है। राजतंत्र, साम्यवाद, लोकतंत्र की सीढ़िया पार कर नये सामजिक शासन व्यवस्था की आवश्यकता दिख रही है।
- किसके जिम्मे है लोकतंत्र ? लोगों के ? रा० ट्राम्प के ? किसान नहीं होते हुए भी किसानों के नेता पर या फिर किसी शाहीन बाग पर।
- हर जगह न्यायतंत्र भी उपस्थित तो था ही।
- दलविहीन राजनीति ही अगली कड़ी है।

113

तलाश : गरीबी और बेरोजगारी

- भारत में इनका निरंतर निवास समझ से परे है।
  यहाँ रोज बढ़ती आवादी के अनुपात में सड़के बनी नहीं,
- हर साल बाढ़ लाने वाली नदियों का पाट बना नहीं,
- इनके किनारे पार्क बने नहीं।
- हर खेत को पानी मिला नहीं।
- दिल्ली, मुंबई मद्रास में भी बाढ़ रोकने के उपाय हुए नहीं।
- उच्च स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन सबको मिला नहीं।
- हर जगह, हर कार्य के लिए उर्जा/बिजली उपलब्ध हुआ नहीं।
- पर्यटन विकसित हुआ नहीं,

क्रमशः

114

तलाश : गरीबी और बेरोजगारी

- औद्योगीकरण हुआ नहीं : जीवन स्तर विकसित देशों के बराबर हुआ नहीं।
  यहाँ तो काम ही काम है करने को, फिर बेरोजगारी कैसी ?
- फिर भी काफी सड़के है, बिजली भी है।
- तरह-तरह के कौशल विकाश की शिक्षा है।
  (जिसके पास भी दो पैसे हैं वह उनसे कुछ कर कराकर उसे बढ़ाना चाहता है। सक्रियता चाहता है।)
- दूर देश में रहने वाले एक अभियंता ने मुझे इसके सही मायने बताया।
  ''गरीब/बेरोजगार सिर्फ वही है जो कामचोर या वेईमान हैं''

क्रमशः

115

तलाश : गरीब और बेरोजगारी

कारण कुछ और भी है –लोगों को काम नहीं

'ना-करी' (नौकरी) चाहिए।- 'बिना काम के वेतन चाहिए।

- हमें वोट दे दो, हम दस लाख नौकरी देगें।
- नहीं हमें दो हम बीस लाख नौकरी देगें - - - किसी ने नहीं कहा सबों को देगें।
- हम कुछ करें नहीं, वेतन भत्ते मिलने चाहिए। कहाँ से ?

''हम मनरेगा'' और तरह-तरह के बिना काम के पेंशन देगें।

''हम तुम्हारे कर्जे माफ कर देगें'' तुम्हारे खातों में घर बैठे बिना काम के पैसे जमा करा देगें।

क्रमशः

116

तलाश : गरीबी और बेरोजगारी

तुम्हारी फैक्टरी बंद हो गयी तुम्हें 'प्रोत्साहन' देगें।

सरकारी, गैर सरकारी उपक्रम तुम्हारी बेईमानी और कामचोरी से बंद हो गए, न इनकी जांच करेंगे, न कमियों की पहचान करेंगे, न दोषारोपण करेंगे।

'स्टिमुलस' देगें।

तुम्हारा वेतन भत्ता कम है, जो करते हो उसे भी बंद कर दो, हड़ताल कर दो, बढ़ा देगें।

क्रमशः

117

तलाश : गरीबी और बेरोजगारी

न्यूनतम काम के बिना न्यूनतम मजदूरी दे देगें ।

जो कुछ लोग काम करना चाहते है उन्हें भी वंद करा दो, देगा कैसे नहीं ?

रोजगार तुम्हारा जनतंत्र सिद्ध) अधिकार जो है, संसार में आपके जीवन का भार काम करने वाले, टैक्स भरने वाले क्यों नहीं उठायेगे भला ।

118

तलाश : जागो ग्राहक जागो !

जाग कर क्या करो ?

मुकदमा करो, वकील करो,
छोटी खरीदारी के लिए
मानसिक शांति भंग करो या चुप चाप सहो ।

- MRP से ज्यादा दाम नहीं देने का ?
- MRP ही न मालूम कितने गुणा बढ़ाकर लिखा हुआ है, उसपर दुकानदार मेहरबानी कर छूट दे देते हैं । (घर से ?) कपड़ा, दवाई, कासमेटिक्स कुछ भी हो ।
- एक दवाई का दाम रु० 16500/-, अस्पताल सप्लाई रु० 12500/- तीन लेने पर लगभग 8000/- ।
- कपड़े में भी यही हाल है।
- ग्राहक कैसे जानेगा कि MRP होना क्या चाहिए ?

क्रमशः

119

तलाश : जागो ग्राहक जागो !

- ❒ बड़े-बड़े सेलेब्रेटी (फिल्मी हस्ती, क्रिकेटर आदि) अत्यंत सामान्य उत्पादन का बड़ी-बड़ी फीस लेकर गलत प्रचार करते हैं ।
- ❒ कई बार हानिकारक प्रचार करते हैं जिसके अनुकरण में कई बच्चों की जाने गयी हैं ।
- ❒ हम उपभोक्ता (Consumer) सबका मूल्य चुकाते है ।
  उपभोक्ता (Consumer) तो Consumed हो गया है ।
- ❒ ग्राहक किस पर क्या करें?

क्रमशः

120

तलाश : जागो ग्राहक !

टी० वी०

- टी० वी० खरीदो, तमाशा देखो कम से कम 'दूरदर्शन' तो देखते थे ।
- अब सेटअप वाक्स लगाओ, हर महीने अच्छा खासा पैसा दो, फिर भी सभी चैनेल देख नहीं सकते ।
- बड़ा से बड़ा टी० वी० खरीदो, परन्तु पूरा स्क्रीन शायद ही दिखाई दे, बगल से, नीचे से प्रचार देखते रहो ।

क्रमशः

121

तलाश : जागो ग्राहक !

- लौटेगें 2 मिनट बाद –
  - ❑ 2 मिनट बाद भी एक झलक के बाद पुन: प्रचार देखें ।
  - ❑ चैनेल बदलो तो सभी पर एक ही समय प्रचार देखो ।
  - ❑ यह मनोरंजन है ? जरुरी जानकारी है ? या प्रचार देख कर झल्लाने, मूड खराब करने के बदले पैसे देते रहें, हर माह ।

122

तलाश : जागो ग्राहक – बिजली सेवा

- लगातार सेवा नहीं मिलती है, तो विभाग क्या करे ? ऊपर से फाल्ट है ।
- Voltage उठा पटक से आपके लाखों रुपये के सामान खराब हो जाय, तो विभाग क्या करे? आप कुछ और व्यवस्था करें ।
- कुछ खराबी होने पर कर्मचारी सुविधा शुल्क लें, तो विभाग क्या करे ? आपको नहीं देना चाहिए (ध्यातव्य : घूस देना, लेने के बराबर का दोष है ।)
- यदि गलत बिल है तो पहले चुका दें, फिर कार्यालय का चक्कर लगाते रहें ।
- गलत बिल आया क्यों ? इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं !
- बिल्कुल उपभोक्ता विरोधी कानून है : जागो ग्राहक जागो का नारा लगाओ, कोई देखनेवाला नहीं ।

क्रमश:

123

तलाश : जागो ग्राहक : शिक्षा सेवा/स्वास्थ्य सेवा ।

- खर्च सीधे GDP का X प्रतिशत .. व्यवस्था और स्तर आप सभी जानते हैं ।
- शिक्षा लेना है ?/ कोचिंग करिए, ट्यूशन करिए या प्राइवेट/पब्लिक स्कूल में पढ़िए ।
- नागरिकों का खर्चा ? बजट प्रावधान से 10x या ज्यदा ।
- शिक्षा 'कर' भरिए, आयकर भरिये, सभी टैक्स भरिये और अपनी शिक्षा की व्यवस्था भी आप खुद करिए ।
- स्वास्थ्य सेवा का भी यही हिसाब है ।

क्रमश:

124

तलाश

प्रशासनिक सेवा : जागो ग्राहक जागो !

- कोई डॉक्टरी तो है नहीं कि बदल लें या फिर थाने से लेकर कई प्रकार के कोर्ट जायें ।
- मुहर/अधिकार तो इसी साहब/चपरासी/कलर्क के पास है । आपको अपना काम करवाना है तो झुकिए चाहे, दिजिये, जैसे भी हो ।

Blank Page

आपकी आलोचना, असहमति, सुझाव का स्वागत है ।

सम्पर्क

अतुल कुमार
मो० - 8935885844
H/3, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग
पटना - 800 020

प्रणव कुमार चौधरी
मो० - 8969481918

डा० अविनाश प्रसाद
मो० - 9934410252

जितना बन पड़ा है शुद्धी का ध्यान रखा है।
इसे पढ़ने वाले/समझने वाले
गलतियों को स्वयं ठीक कर लेने की कृपा करें।

✧ विनीत एवं क्षमाप्रार्थी
डॉ० विश्वेन्द्र कुमार सिन्हा

तलाश एक आन्दोलन